www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 272 | जौनपुर शनिवार, 23 मई 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

महंगाई–बेरोजगारी से जनता परेशान, पीएम मोदी विदेश यात्रा में व्यस्त : आनंद दुबे

मुंबई, (एजेंसी)। शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता आनंद दुबे ने गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जनता यहां महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हो रही है और पीएम मोदी हैं कि विदेश दौरे में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 दिनों से प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पर थे और इस दौरान देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और आम लोगों की परेशानियां जैसे मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया। दुबे ने आरोप लगाया कि सरकार की प्राथमिकताएं जनता की समस्याओं से अलग दिखती हैं और सिर्फ दिखावे की राजनीति की जाती है। उनके अनुसार, जनता अब इन बातों को समझने लगी है और धीरे–धीरे असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि देश में आर्थिक स्थिति को लेकर लोगों में चिंता है। उनके मुताबिक महंगाई बढ़ रही है, रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं और आम परिवारों का बजट प्रभावित हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि ऐसे हालात में सरकार की ओर से जो संदेश दिए जाते हैं, वे वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाने जैसे लगते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले 2029 के चुनावों में जनता इसका जवाब अच्छे से देगी। कश्मीर मुद्दे पर भी उन्होंने टिप्पणी की और कहा कि भारत का रुख पाकिस्तान के प्रति सख्त होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है ।

मध्य प्रदेश में पेसा प्रेरकों की सेवाएं निरंतर जारी रखी जाए : उमंग सिंघार

भोपाल, (एजेंसी)। मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से पेसा एक्ट के क्रियान्वयन के लिए नियुक्त पेसा प्रेरकों की सेवाएं निरंतर जारी रखने की मांग की है। उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को लिखे पत्र में कहा है कि मध्यप्रदेश में पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 (पेसा एक्ट) के क्रियान्वयन हेतु प्रेरकों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा अपने बजट से इनकी सेवाएं जारी न रखते हुए सेवा समाप्त कर दी गई है।उन्होंने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश के आदिवासी जिलों में कार्य प्रभावित होंगे। पत्र में उल्लेख किया गया है कि शिवराज सिंह चौहान सरकार के दौरान प्रेरकों की नियुक्ति हुई थी तथा 15 नवम्बर 2022 को राष्ट्रपति द्वारा इसका औपचारिक शुभारंभ किया गया था। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि पेसा एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन एवं लगभग पांच हजार प्रेरकों के हित को ध्यान में रखते हुए उनकी सेवाएं निरन्तर जारी रखने के संबंध में ठोस निर्णय लिया जाए।सिंघार ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक झटके में हजारों मोबिलाइजर्स की नौकरियां खत्म कर दीं।

पीएम मोदी बोले-सार्थक रही मीटिंग, विकसित भारत के लिए सुधारों पर हुई विस्तृत चर्चा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक के एक दिन बाद शुक्रवार को बैठक में लिए गए फैसलों और चर्चा की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैठक बेहद सार्थक रही, जिसमें 'ईज ऑफ लिविंग' और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को और बेहतर बनाने तथा सुधारों को आगे बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश दौरे से लौटने के बाद गुरुवार शाम 5 बजे 'सेवा तीर्थ' में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। यह साल 2026 की पहली पूर्ण मंत्रिपरिषद बैठक थी। इसमें सभी कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्यमंत्री शामिल हुए। पिछली ऐसी पूर्ण बैठक 4 जून 2025 को आयोजित की गई थी। "कल

मंत्रिपरिषद की एक सार्थक बैठक हुई। हमने 'ईज ऑफ लिविंग' और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने से जुड़े विचारों और बेहतरीन तौर–तरीकों का आदान–प्रदान किया। इस बात पर चर्चा की कि 'विकसित भारत' के हमारे साझा सपने को साकार करने के लिए सुधारों को और आगे कैसे बढ़ाया जाए।" यह बैठक अमेरिका–ईरान युद्ध के कारण उत्पन्न वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, ईंधन आपूर्ति में संभावित रुकावटों, महंगाई और बढ़ते तेल मूल्यों की पृष्ठभूमि में हुई। सरकार इन परिस्थितियों पर लगातार नजर रखे हुए है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि वे ईंधन का समझदारी से उपयोग करें। इसमें वर्क फ्रॉम होम, अधिक ऑनलाइन मीटिंग्स, कम से कम एक साल तक सोना खरीदने से परहेज और अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचना शामिल है। सरकार का फोकस आर्थिक स्थिरता बनाए रखते हुए सुधारों को तेज करने पर है।

पीएम मोदी की अपील पर सिंधिया ने पेट्रोल–डीजल वाहनों का उपयोग न करने का किया आग्रह

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'ऊर्जा बचत' अपील पर क्षेत्रवासियों और समर्थकों से अपील करते हुए कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में पेट्रोल–डीजल की प्रत्येक बूंद बचाना हम सभी का राष्ट्रीय दायित्व है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और आह्वान के अनुरूप सार्वजनिक जीवन में सादगी, जिम्मेदारी और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को अपनाना समय की आवश्यकता है। इसी भावना के साथ उन्होंने भोपाल और संसदीय क्षेत्र गुना, शिवपुरी में समर्थकों से प्रवास में उनके आवागमन के दौरान पेट्रोल–डीजल वाहनों का उपयोग न करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनता का स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है तथा देशहित में बचाया गया ईंधन राष्ट्र के प्रति हमारी संवेदनशीलता

और जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। सिंधिया ने क्षेत्रवासियों से जिम्मेदार नागरिक के रूप में सहभागिता निभाने का आग्रह करते हुए कहा कि सामूहिक छोटे प्रयास भी राष्ट्रहित में बड़े परिवर्तन का आधार बनते हैं। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, "क्षेत्र की देवतुल्य जनता से आत्मीय अपील, आप सभी को ज्ञात है कि आज मैं दो दिवसीय अपने ससंदीय क्षेत्र के गुना–अशोकनगर–शिवपुरी प्रवास पर आप सबके बीच आ रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के अनुसार, वैश्विक परिस्थितियों के इस दौर में पेट्रोल–डीजल की एक–एक बूंद बचाना हम सभी का राष्ट्रीय कर्तव्य है। इसी भावना के साथ मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह है कि मेरे आवागमन के दौरान पेट्रोल–डीजल वाहनों का उपयोग न करें।

राहुल गांधी सच बोलते हैं तो भाजपा को तकलीफ होती है : सीएम सुक्खू

शिमला, (एजेंसी)। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के उस बयान का बचाव किया है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में उन मुद्दों को उठाते हैं जिनका संबंध आम जनता से होता है।

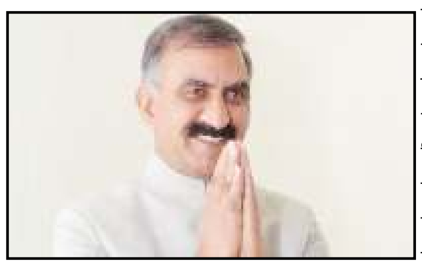

वह सच बोल रहे हैं, इसलिए भाजपा को तकलीफ हो रही है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि ये बातें जनता के बीच जाएं। राहुल गांधी की बातों के केंद्र में देश की चुनौतियां और जनहित के विषय होते हैं। दूसरी ओर, पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर सीएम ने उनके दूरदर्शी नेतृत्व, देश के तकनीकी एवं आधुनिक विकास में दिए गए अमूल्य योगदान तथा युवाओं को सशक्त बनाने के उनके संकल्प को कृतज्ञतापूर्वक स्मरण किया। राजीव गांधी के विचार, मूल्य और राष्ट्र–निर्माण के प्रति उनका समर्पण आज भी हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राजीव गांधी ने जिस आधुनिक, आत्मनिर्भर और युवा भारत का सपना देखा था, उसे हमारी सरकार राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के माध्यम से आगे बढ़ा रही है। इस योजना के तहत युवाओं को ई–टैक्सी खरीदने पर 50 फीसदी सब्सिडी दी जा रही है। वर्ष 2026–27 में 500 युवाओं को इससे जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

भारतीय कंपनियां अमेरिकी हाईटेक कंपनियों के साथ करें जॉइंट वेंचर – नितिन गडकरी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारतीय कंपनियों को नवीनतम तकनीकों तक पहुंच हासिल करने के लिए अमेरिकी कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम (जॉइंट वेंचर) करने की जरूरत है। कल गुरुवार को अमेरिकन चौंबर ऑफ कॉमर्स के वार्षिक लीडरशिप समिट को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा, "भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि अमेरिकी कंपनियां नई तकनीकों का विकास कर रही हैं। ऐसे में भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिकी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करना बेहद जरूरी है।" उन्होंने

कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय हाईवे परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने में अमेरिकी कंपनियों से परामर्श लेने पर भी विचार कर रहा है। गडकरी ने कहा कि लॉजिस्टिक्स में सप्लाई चेन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और एक्सप्रेसवे तथा आर्थिक कॉरिडोर के तेजी से विस्तार के कारण भारत में लॉजिस्टिक्स लागत अब एकल अंक (सिंगल डिजिट) तक पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि आईआईटी चेन्नई, आईआईटी कानपुर और आईआईएम बेंगलुरु द्वारा तैयार ताजा अध्ययन के अनुसार, एक्सप्रेसवे और आर्थिक कॉरिडोर के निर्माण से भारत की लॉजिस्टिक्स लागत 16 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत रह गई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय देशों में लॉजिस्टिक्स लागत 12 प्रतिशत है, जबकि चीन में यह 8 से 10 प्रतिशत के बीच है। गडकरी ने यह भी कहा कि सरकार अगले पांच वर्षों में भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर–1 बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। उन्होंने कहा, "जब मैंने परिवहन मंत्री का कार्यभार संभाला था, तब भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग का आकार 14 लाख करोड़ रुपये था।

पश्चिम एशिया संकट के बीच ओडिशा की पहल, ईंधन संरक्षण के लिए 8 सूत्रीय निर्देश जारी

भुवनेश्वर, (एजेंसी)। पश्चिम एशिया में बने हालात और ईंधन खपत को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच ओडिशा सरकार ने पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राज्य के सभी सरकारी विभागों और कार्यालयों के लिए 8 सूत्रीय निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ईंधन संरक्षण को लेकर चर्चा की थी। इसके बाद उन्होंने अपने आधिकारिक काफिले में वाहनों की संख्या कम की थी और आम लोगों से भी ईंधन की बचत करने की अपील की थी।मुख्यमंत्री ने गुरुवार को मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि सरकारी कामकाज में पेट्रोल

और डीजल की खपत कम करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। सरकार द्वारा जारी 8 प्रमुख निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें वर्चुअल बैठकों को बढ़ावा, सरकारी दफ्तरों में इलेक्ट्रिक वाहनों की अनिवार्यता, वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कारपूलिंग, वाहन उपयोग को लेकर नई गाइडलाइन, आधिकारिक दौरों में सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता, निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग की योजना, सरकारी कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा और ईंधन खपत में 10 प्रतिशत कटौती का लक्ष्य शामिल है। निर्देश के मुताबिक, सरकारी बैठकें, समीक्षा बैठकें, प्रशिक्षण कार्यक्रम और वर्कशॉप अब अधिकतर वर्चुअल मोड में आयोजित किए जाएंगे। केवल जरूरी अधिकारियों को ही शारीरिक रूप से उपस्थित रहने की अनुमति होगी। 1 जून से सरकारी कार्यालयों द्वारा खरीदे जाने वाले सभी नए दोपहिया और चारपहिया वाहन इलेक्ट्रिक होंगे। विशेष परिस्थितियों में ही पेट्रोल या डीजल वाहन खरीदने की अनुमति मिलेगी। सरकारी वाहन सुविधा पाने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को कारपूलिंग अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे वाहनों के लिए ईंधन आवंटन भी आधा किया जाएगा। वित्त विभाग को 15 दिनों के भीतर यह तय करने के निर्देश दिए गए हैं ।

मुख्यमंत्री मोहन यादव के आह्वान पर गंगा दशहरा पर जन आंदोलन बनेगा जल गंगा संवर्धन अभियान

भोपाल, (एजेंसी)। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हिंदू संस्कृति के अनुसार गंगा दशहरा का पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी और प्रकृति एवं जन–जीवन को धन्य किया था। इस वर्ष गंगा दशहरा के पावन अवसर पर प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान को व्यापक स्वरूप देते हुए जन–जन को जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अभियान केवल शासकीय कार्यक्रम तक सीमित न रखकर जनभागीदारी आधारित व्यापक अभियान बनाया जाए। उन्होंने कहा कि पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण भविष्य की आवश्यकता है और इसमें समाज के हर वर्ग की सक्रिय सहभागिता जरूरी है।मुख्यमंत्री मोहन यादव के इसी विजन के अनुक्रम में गंगा दशहरा के पावन अवसर पर 25 मई को प्रदेश के सभी जिलों के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में

भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि "जल गंगा संवर्धन अभियान" प्रदेश में 19 मार्च से 30 जून 2026 तक संचालित किया जा रहा है। गंगा दशहरा पर आयोजित कार्यक्रमों में जिले के प्रभारी मंत्री शामिल होंगे। कार्यक्रम के प्रथम चरण में जनसहभागिता से जल संरक्षण एवं जल संवर्धन से जुड़े कार्य किए जाएंगे। इसके बाद द्वितीय चरण में गंगा दशहरा विषय पर आधारित सांस्कृतिक संध्या आयोजित की जाएगी।

असम में गो–चोरी और तस्करी पर शिकंजा, जनवरी से अब तक 425 केस दर्ज

गुवाहाटी, (एजेंसी)। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने राज्य में पशु तस्करी और गो चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि असम सरकार की श्जीरो टॉलरेंसश नीति के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है और आगामी त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि जनवरी 2026 से अब तक राज्य में गो–चोरी और पशु तस्करी के मामलों में 856 लोगों को

गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान 425 मामले दर्ज किए गए हैं।उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान 4355 मवेशियों को बरामद किया गया, जबकि 2980 किलोग्राम से ज्यादा बीफ भी जब्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पशु तस्करी, गो–चोरी और अवैध बीफ कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि आगामी त्योहार को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, यह कार्रवाई 1 जनवरी से 19 मई 2026 के बीच की गई है। असम पुलिस और अन्य एजेंसियां राज्य में पशु तस्करी और अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चला रही हैं।इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा था कि राज्य सरकार आने वाले विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बिल पेश करने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार असम में यूसीसी कानून लाने की अपनी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है और विश्वास जताया कि यह बिल विधानसभा में पारित हो जाएगा।

सीएम भजन लाल शर्मा ने अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए

जयपुर, (एजेंसी)। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अवैध धर्मांतरण में शामिल लोगों और राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।राजनीतिक विश्लेषण सेवा बांसवाड़ा में एक जिला–स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने जिले में चंदन के जंगलों को विकसित करने की भी घोषणा की। इसके तहत श्हरियालो राजस्थानश अभियान के तहत हर तय वन क्षेत्र में चंदन के 11,000 पौधे लगाए जाएंगे।उन्होंने वन विभाग को पौधारोपण अभियान में तेजी लाने और वनों के संरक्षण व विस्तार की दिशा में प्रयासों को

और तेज करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे जमीनी स्तर पर निरीक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे ज्यादा गंभीरता से करें और लोगों की शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करें। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के अपने तीन–दिवसीय दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट सभागार में एक जिला–स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उन्होंने जिले में लागू की जा रही सरकारी योजनाओं, बजट घोषणाओं, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और जन कल्याण कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की।सीएम शर्मा ने अधिकारियों को संवेदनशीलता, जवाबदेही और समर्पण के साथ काम करने का निर्देश दिया, ताकि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक जमीनी स्तर पर बिना किसी देरी के पहुंच सके। बांसवाड़ा नगर परिषद आयुक्त दुर्गेश सिंह रावत के कामकाज पर असंतोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद स्थानीय स्वशासन विभाग ने आदेश जारी कर आयुक्त को श्पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षाश स्थिति में डाल दिया।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे जमीनी दौरे बढ़ाएं, स्थानीय मुद्दों का स्वतंत्र रूप से संज्ञान लें, और नियमित निगरानी व प्रशासनिक समन्वय के माध्यम से उनका समय पर समाधान सुनिश्चित करें।

संपादकीय

नीतिगत बहसें हाशिये पर चली गई

पहले चुनाव बिल्कुल दोषमुक्त होते थे ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन तब उन्हें ऐसे युद्ध की तरह भी नहीं लड़ा जाता था, जिसमें विरोधी को समूल नष्ट कर देने की भावना हो। कभी चुनाव को लोकतंत्र का उत्सव समझा जाता था। तब चुनाव बिल्कुल दोषमुक्त थे या वे पूरी तरह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से आयोजित होते थे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन तब उन्हें ऐसे युद्ध की तरह भी नहीं लड़ा जाता था, जिसमें विरोधी को समूल नष्ट कर देने की भावना हो। अब ऐसा ही नजारा खास कर वैसे राज्य में देखने को मिलता है, जहां कोई गैर–भाजपा दल अब तक मजबूती से खड़ा रहा हो। पश्चिम बंगाल में इस बार विधानसभा चुनाव कुछ ऐसे ही माहौल में संपन्न हुआ। एसआईआर प्रक्रिया सहित अन्य मामलों में निर्वाचन आयोग की विवादित भूमिका से लेकर अर्धसैनिक बलों द्वारा घेराबंदी और केंद्रीय जांच एजेंसियों की एकतरफा जैसी दिखने वाली कार्रवाइयों के निशाने पर ममता बनर्जी रहीं। भाजपा नेतृत्व ने अब अपनी पहुंच से बाहर रहे इस किले को जीत लेने की व्यूह–रचना में किसी राजनीतिक मान–मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। ये कहने का अर्थ कतई यह नहीं है कि ममता बनर्जी नैतिक या मर्यादित राजनीति करती हैं। उनकी सियासत में भी बाहुबल और तोड़–जोड़ का उतना ही पुट रहा है। उनकी सफलता में ऐसे रुझानों का योगदान है। बहरहाल, यही ध्यान देने की बात है। अब चुनावों में ऐसी प्रवृत्तियां ही निर्णायक महत्त्व की हो गई हैं। इसका शिकार विकास और राष्ट्र–निर्माण से संबंधित मुद्दे बने हैं। नीतिगत बहसें हाशिये पर चली गई हैं। जन–कल्याण के नाम पर अधिक से अधिक यही नजर आता है कि तमाम पार्टियां बैंक खातों में नकदी डालने के वादे बढ़–चढ़ कर करती हैं। उन्हें उससे भी ज्यादा भरोसा जाति–धर्म जैसे बांटने वाले मुद्दों पर लोगों को गोलबंद करने की रणनीति पर रहता है। ऐसे संकेत हैं कि इस बार केरल के विधानसभा चुनाव में भी ऐसे पहचान–गत मुद्दे प्रमुख हो गए। यानी जिस राज्य की राजनीतिक चर्चा के केंद्र में शिक्षा और स्वास्थ्य, और विकास संबंधी योजनाएं रहती थीं, वहां भी अगड़े– पिछड़े, हिंदू– मुस्लिम– ईसाई जैसी अस्मिताओं पर ध्रुवीकरण के संकेत मिले। ऐसे में उत्सव जैसे माहौल का गायब हो जाना लाजिमी ही है। उलटे अब हर चुनाव एक तरह का जख्म छोड़ कर जाने लगा है!

बहुपक्षवाद का संकट और डब्लूटीओ में सुधार की अनिवार्यता

राजेश अग्रवाल

बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली औचित्य के गहरे संकट का सामना कर रही है। बीसवीं सदी के उत्तरार्ध और इक्कीसवीं सदी की शुरुआत में, विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) वैश्विक व्यापार का केंद्रीय स्तंभ था, जो नियम–आधारित व्यवस्था की पेशकश करने के साथ तटस्थता, पूर्वानुमेयता और निष्पक्षता का वादा करता था। हालांकि आज, ये वादे काफी कमजोर प्रतीत होते हैं। डब्लूटीओ में विश्वास की कमी, किसी एक विफलता का परिणाम नहीं है, बल्कि यह संरचनात्मक असंतुलन, असमान प्रवर्तन और वैश्विक आर्थिक शक्ति के बदलते स्वरुप के संचयी प्रभाव को प्रतिबिंबित करती है। इस संकट के मूल में है – वैश्विक उत्पादन का अत्यधिक केंद्रीकरण और आक्रामक व्यापार प्रथाओं की निरंतरता। समय के साथ, आपूर्ति श्रृंखलाएँ परस्पर अत्यधिक निर्भर हो गई हैं और उनका वितरण भी असमान है, जहाँ कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अनुपात से कई गुनी ज्यादा नियंत्रण रखती हैं। हालांकि, इस केंद्रीकरण ने कुछ मामलों में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक कुशल बना दिया है, लेकिन इसने उन्हें काफी हद तक कमजोर भी बना दिया। व्यवधानकृचाहे भू–राजनीतिक हो, आर्थिक हो, या पर्यावरण–संबंधी होंकृअब प्रणालीगत नतीजे लेकर आते हैं। परिणामस्वरूप, आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरी अब केवल एक आर्थिक चिंता के रूप में नहीं देखी जातीय इसे अब राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक अस्तित्व के मामले के तौर पर देखा जाने लगा है। धारणा में हुए बदलाव ने नीतिगत प्रतिक्रियाओं की एक ऐसी लहर को जन्म दिया है, जो बहुपक्षवाद के मौलिक सिद्धांतों को चुनौती देती हैं। देश घरेलू हितों की रक्षा के लिए संरक्षण उपायों, आक्रामक औद्योगिक नीतियों और निर्यात नियंत्रण को अपना रहे हैं। हालांकि ऐसी रणनीतियाँ अल्पकालिक सहनशीलता ला सकती हैं, लेकिन वे डब्लूटीओ की सहयोग भावना और कानूनी रूपरेखा को अक्सर कमजोर कर देती हैं। तकनीकी अवरोध, महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं पर नियंत्रण और भू–राजनीतिक प्रभाव के उपकरण के रूप में बाजार पहुंच का बढ़ता उपयोग एक व्यापक परिवर्तन का संकेत देता हैरू व्यापार अब केवल आर्थिक लेन–देन ही नहीं, बल्कि रणनीतिक शक्ति के बारे में है। डब्लूटीओ सदस्यों के बीच एक व्यापक रूप से मान्य दृष्टिकोण यह है कि संगठन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को उनके प्रतिबद्धताओं के प्रति जवाबदेह ठहराने में अक्षम रहा है और इसने वर्तमान स्थिति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जब नियम असमान रूप से लागू किए जाते हैं या प्रवर्तन तंत्र विफल हो जाते हैं, तो प्रणाली में विश्वास कमजोर हो जाता है। कई देशों में, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों में, यह धारणा मजबूत हुई है कि डब्लूटीओ अब एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करता। इसके बजाय, इसे एक ऐसे संस्थान के रूप में देखा जाता है, जो तेजी से बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था की वास्तविकताओं के प्रति अनुकूल होने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस संदर्भ में, सुधार प्रयासों का केंद्रीय उद्देश्य डब्लूटीओ की विश्वसनीयता को बहाल करना हो गया है। यद्यपि डब्लूटीओ सुधार की आवश्यकता पर सदस्यों के बीच व्यापक सहमति है, फिर भी इसे हासिल करने के तरीके पर सहमति न के बराबर है। सुधार की संरचना और विषय वस्तु पर बहसें लगातार विवादास्पद होती जा रही हैं। याओंडे के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में, सदस्यों ने डब्लूटीओ के मूलभूत सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनरू पुष्टि की, जिनमें निष्पक्षता, पारदर्शिता, समावेश और सहमति–आधारित निर्णय शामिल हैं। इन सिद्धांतों ने लंबे समय से डब्लूटीओ को अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से अलग बनाये रखा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी सदस्य, चाहे उनका आकार या उनकी आर्थिक शक्ति कुछ भी हो, वैश्विक व्यापार नियमों को अंतिम रूप देने में अपनी बात रख सकें। हालांकि, इन सिद्धांतों के व्यावहारिक अनुप्रयोग को, विशेष रूप से बहुपक्षीय समझौतों से जुड़ी चर्चाओं में, समस्याओं का सामना करना पड़ा है। ये समझौते डब्लूटीओ सदस्यों के उपसमूहों के बीच बातचीत के बाद तैयार किए गए हैं। इन्हें कई देशकृविशेष रूप से वैश्विक उत्तर के देश कृ सहमति–आधारित नियम निर्माण की चुनौतियों का व्यावहारिक समाधान मानते हैं। ऐसी सदस्यता के लिए, जहां विकास स्तर और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में व्यापक असमानताएँ मौजूद हैं, जटिल मुद्दों पर सर्वसम्मति प्राप्त करना कठिन होता जा रहा है। बहुपक्षीय समझौते आगे बढ़ने का एक तरीका प्रदान करते हैं, जिससे इच्छुक प्रतिभागी नए नियम स्थापित कर सकते हैं, इसमें उन देशों को रुकावट नहीं माना जाता, जो प्रतिबद्ध होने के लिए अभी तैयार नहीं हैं, ऐसी ही प्रणाली डब्लूटीओ से पहले गैट, 1947 (टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता) के तहत अस्तित्व में थी। इस मुद्दे पर भारत का रुख एक सावधानीपूर्वक तैयार संतुलनकारी कार्य को दर्शाता है।

अपराधमुक्त राजनीति से ही संभव है नया भारत-विकसित भारत

ललित

भारत आज एक ऐतिहासिक संक्रमण काल से गुजर रहा है। एक ओर देश विकसित भारत–2047 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, वैश्विक मंचों पर भारत की प्रतिष्ठा निरंतर बढ़ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व राजनीति और कूटनीति के केंद्र में उभर रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय राजनीति में अपराध, धनबल और बाहुबल की बढ़ती पैठ लोकतंत्र की आत्मा को आहत कर रही है। यह विडंबना ही है कि जिस भारत को विश्वगुरु बनने का स्वप्न दिखाया जा रहा है, उसकी राजनीति अभी भी अपराधमुक्त नहीं हो सकी है। हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद सामने आए आंकड़ों ने इस चिंता को और गहरा कर दिया है। समाचार पत्रों में प्रकाशित एडीआर (ऐसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिपोर्ट) की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल विधानसभा के लगभग 65 प्रतिशत विधायक आपराधिक मामलों वाले हैं, जबकि 61 प्रतिशत विधायक करोड़पति हैं। रिपोर्ट के अनुसार 294 विधायकों में से 190 विधायकों ने अपने विरुद्ध आपराधिक मामले घोषित किए हैं तथा लगभग 142 विधायकों पर गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, महिलाओं के विरुद्ध अपराध और अन्य गंभीर मामले भी शामिल हैं। यह केवल पश्चिम बंगाल की स्थिति नहीं है। संसद और देश की अनेक विधानसभाओं की स्थिति भी इससे बहुत अलग नहीं है। पिछले कुछ वर्षों के चुनावी विश्लेषण बताते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित अनेक राज्यों में बड़ी संख्या में ऐसे जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं जिन पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं। लोकतंत्र के मंदिरों में अपराध और दागी छवि वाले लोगों की बढ़ती उपस्थिति आज राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुकी है। राजनीति मूलतः लोकसेवा, नैतिक नेतृत्व और राष्ट्रनिर्माण का माध्यम मानी गई थी। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं ने राजनीति को मूल्य आधारित दिशा दी। लेकिन समय के साथ राजनीति में वैचारिक प्रतिबद्धता का स्थान धीरे–धीरे चुनावी गणित, धनबल और प्रभावशाली समूहों ने लेना शुरू कर दिया। आज कई राजनीतिक दल उम्मीदवार चयन में योग्यता, चरित्र और जनसेवा की बजाय "जीतने की क्षमता" को प्राथमिकता देते दिखाई देते हैं। यही कारण है कि दागी छवि वाले व्यक्तियों को भी टिकट देने में संकोच नहीं किया जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की राजनीति में आने के बाद अनेक मंचों से राजनीति के अपराधीकरण पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने संसद में और सार्वजनिक मंचों पर कई बार कहा कि राजनीति को अपराधमुक्त बनाना लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष अदालतों की आवश्यकता पर बल दिया। किंतु चिंता का विषय यह है कि आज भी लगभग सभी राजनीतिक दलों की स्थिति समान दिखाई देती है। चुनाव जीतने की मजबूरी और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण दल अपराधी और दागी उम्मीदवारों को टिकट देने से परहेज नहीं कर पा रहे हैं। इस स्थिति के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है चुनावों का अत्यधिक खर्चीला होना। आज चुनाव लड़ना सामान्य व्यक्ति की क्षमता से बाहर होता जा रहा है। बड़े संसाधनों वाले और आर्थिक रूप से प्रभावशाली लोग चुनावी प्रक्रिया में अधिक सक्रिय हो रहे हैं। दूसरा कारण है बाहुबल और प्रभाव का उपयोग। कई क्षेत्रों में आज भी राजनीतिक प्रभाव स्थापित करने के लिए शक्ति प्रदर्शन को महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरा कारण है न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति। गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों के वर्षों तक लंबित रहने के कारण आरोपी चुनाव लड़ते रहते हैं और जनप्रतिनिधि बन जाते हैं। राजनीति में अपराधीकरण का दूसरा बड़ा पक्ष है धनबल। पश्चिम बंगाल विधानसभा के आंकड़े बताते हैं कि 61 प्रतिशत विधायक करोड़पति हैं। यह प्रवृत्ति पूरे देश में दिखाई देती है। संसद और विधानसभाओं में करोड़पति जनप्रतिनिधियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रश्न यह है कि क्या लोकतंत्र धीरे–धीरे सामान्य नागरिक की पहुंच से दूर होता जा रहा है? यदि राजनीति केवल धनवान और प्रभावशाली वर्गों तक सीमित हो जाएगी तो लोकतंत्र की समावेशी भावना कमजोर होगी। इन परिस्थितियों में नागरिक समाज और लोकतांत्रिक संगठनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारतीय मतदाता संगठन इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास कर रहा है। इसके संस्थापक रिखबचंद जैन के नेतृत्व में लंबे समय से राजनीति को स्वच्छ और अपराधमुक्त बनाने की दिशा में जनजागरण अभियान चलाए जा रहे हैं। संगठन मतदाता जागरूकता, नैतिक मतदान, स्वच्छ राजनीति और जिम्मेदार नागरिकता को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। लोकतंत्र को केवल चुनावी प्रक्रिया नहीं, बल्कि मूल्य आधारित व्यवस्था मानते हुए यह संगठन समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है कि मतदाता केवल जाति, धर्म, क्षेत्र या दलगत निष्ठा के आधार पर नहीं, बल्कि उम्मीदवार के चरित्र और सार्वजनिक जीवन को देखकर मतदान करें। इसी प्रकार एडीआर (ऐसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिपोर्ट) जैसे संगठन भी चुनावी पारदर्शिता और जनप्रतिनिधियों की पृष्ठभूमि सार्वजनिक करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इन संगठनों के कारण आज मतदाताओं को उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों, संपत्ति और शिक्षा संबंधी जानकारी उपलब्ध हो रही है। यह लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय चुनाव आयोग भी इस दिशा में लगातार प्रयासरत है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गए हैं। उम्मीदवारों को शपथपत्र में अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति और देनदारियों की जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। चुनाव आयोग लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चला रहा है। किंतु केवल औपचारिक प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। इन प्रयासों को अधिक तीव्र, व्यापक और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है कि राजनीति के अपराधीकरण के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक आंदोलन खड़ा किया जाए। इसके लिए कुछ ठोस कदम आवश्यक हैं– पहला, जिन उम्मीदवारों पर हत्या, बलात्कार, अपहरण, भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप न्यायालय द्वारा तय हो चुके हों।

ट्रंप–नेतन्याहू के बीच हुआ झगड़ा, ईरान को कैसे इससे मिल गया बड़ा मौका

अभिनय

ईरान को घुटनों पर लाने के लिए जिस अमेरिका और इजराइल ने कंधे से कंधा मिलाकर बम बरसाए थे, आज वही दोनों महाशक्तियां आपस में भिड़ गई हैं। वजह कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि वही ईरान है जिस पर दोनों मिलकर फतह पाना चाहते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच 19 मई की रात हुई एक सीक्रेट फोन कॉल ने दोनों देशों के रिश्तों में छिपे तनाव को दुनिया के सामने ला दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह बातचीत इतनी तीखी थी कि इसके बाद नेतन्याहू गुस्से से तमतमा उठे थे। अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स सीएनएन और एग्जिओस ने खुफिया सूत्रों के हवाले से इस महा–तनाव की इनसाइड स्टोरी पब्लिश की है। सूत्रों के मुताबिक, करीब एक घंटे चली इस मुश्किल कॉल के बाद नेतन्याहू का पारा सातवें आसमान पर था। अमेरिकी अधिकारियों ने तंज कसते हुए कहा कि कॉल के बाद बीबी (नेतन्याहू) के बालों में आग लग गई थी। नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान के सैन्य ठिकानों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दोबारा भीषण हमले किए जाएं ताकि वह संभल न सके। वहीं, ट्रंप ने ऐन वक्त पर हमलों को रोक दिया है। वह कतर, सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे खाड़ी मध्यस्थों द्वारा तैयार श्लेटर ऑफ इंटेंटश को मौका देना चाहते हैं, जिसके तहत 30 दिनों के लिए युद्ध विराम और बातचीत का रास्ता खुल सके। इस तनातनी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सामने एक ऐसा बयान दे दिया, जिसने इजराइल की संप्रभुता और नेतन्याहू के ईगो पर गहरी चोट की है। ट्रंप ने कैमरे पर बेबाकी से कह दिया बेंजामिन नेतन्याहू वही करेंगे, जो मैं उनसे चाहूंगा। नेतन्याहू का मानना है कि ट्रंप का यह यू–टर्न ईरान को परमाणु हथियार बनाने और मिसाइलें रीग्रुप करने का समय दे रहा है। फिलहाल, इस श्पावर स्ट्रगलश ने यह साफ कर दिया है कि ईरान वॉर के अगले कदम को लेकर वाशिंगटन और तेल अवीव के बीच सबकुछ ठीक नहीं है। 19 मई 2026 की तारीख वाइट हाउस और यरूशलम फोन लाइन से जुड़े। करीब 1 घंटे तक डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की बात हुई। एग्जिओस की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू इस कॉल के दौरान परेशान नजर आए। बहुत हद तक इसका कारण है 17 मई का दिन। इस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को भरोसा दिलाया था कि अमेरिका मंगलवार यानी 19 मई को ईरान पर नए और घातक हमलों की शुरुआत करेगा। इजराइल इसी की उम्मीद में बैठा था। लेकिन 24 घंटे के भीतर ट्रंप ने यू टर्न ले लिया क्योंकि कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी ने ऐसे हमले ना करने का अनुरोध किया था। ऐसे में नेतयाहू ने कहा कि हमलों को टालना एक बहुत बड़ी गलती है और इससे केवल ईरान को अपनी सैन्य ताकत फिर से संगठित करने का समय मिलेगा। एग्जिओस ने एक अमेरिकी सूत्र के हवाले से दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत की जानकारी छापी है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि मीडिएटर एक लेटर ऑफ इंटेंट पर काम कर रहे हैं जिस पर अमेरिका और ईरान दोनों साइन करेंगे। जिसका मकसद युद्ध को औपचारिक रूप से खत्म करना है। साथ ही इसके जरिए ईरान के एटम प्रोग्राम और स्टेट ऑफ फोरमच को खोलने जैसे मुद्दों पर 30 दिनों की बातचीत शुरू होगी। दो इजराइली सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि दोनों नेता ईरान को लेकर आगे के प्लान पर एकमत नहीं हैं। सोर्सेस का कहना है कि वाशिंगटन में इजराइल के राजदूत ने अमेरिकी सांसदों को जानकारी दी थी कि नेतन्या इस बातचीत को लेकर चिंतित थे। हालांकि दूतावास के एक प्रवक्ता ने एक्सियोस को इस बात से इंकार किया और कहा राजदूत निजी बातचीत पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। दरअसल अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर दोबारा हमला करने का प्लान बनाया था। इस बार होने वाले ऑपरेशन को नया नाम दिया गया था। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देश ईरान के खिलाफ ऑपरेशन स्लेज हैमर शुरू करने वाले थे। इसी प्लानिंग की वजह से नेतयाओं को लग रहा था कि वह अपना एकमेव लक्ष्य हासिल कर लेंगे। यानी ईरान को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ना आए तो किरदार का नाम ट्रंप का आएगा। ट्रंप ने ऐन वक्त पर ऑपरेशन स्लेज हैमर को टाल दिया। ट्रंप ने 18 मई को सोशल मीडिया पर लिखा कि वो ईरान पर 1 घंटे में ही हमला कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे और डिप्लोमेसी के लिए वक्त देंगे। बस यह ट्विस्ट नेऊ के लिए टेंशन बन गया। क्योंकि जिन ट्रंप के बारे में कहा जाता था कि ईरान पर हुए हमले में इजराइल ने जैसा चाहा अमेरिका ने वैसा ही बिहेव किया। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत अंतिम चरण में है, जबकि तेहरान ने पाकिस्तान के जरिए मिले नए अमेरिकी प्रस्ताव की समीक्षा शुरू कर दी है। ईरान ने अपनी शर्तों में विदेशों में फसी संपत्तियों की रिहाई और ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी खत्म करने की मांग दोहराई है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने निर्देश दिया है कि देश का हथियार–ग्रेड समृद्ध यूरेनियम किसी भी हालत में विदेश नहीं भेजा जाएगा। दो वरिष्ठ ईरानी सूत्रों के हवाले से यह दावा सामने आया है। इस रुख से अमेरिका–ईरान के बीच चल – रही शांति वार्ता में नया पेंच फंस सकता है। इसकी वजह अमेरिका–इजराइल की प्रमुख मांगों में ईरान के यूरेनियम को दूसरे देश में भेजना शामिल है। अमेरिकी खुफिया आकलन के मुताबिक ईरान सैन्य क्षमता तेजी से खड़ी कर रहा है। युद्धविराम के दौरान उसने ड्रोन प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है। – अनुमान है कि वह 6 महीने में ड्रोन हमले की – क्षमता बहाल कर लेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि –ईरान नष्ट हुई मिसाइल साइट्स, लॉन्चर्स व हथियार उत्पादन क्षमता को भी जल्द तैयार कर लेगा। अमेरिका ने अपना रवैया बदल दिया है। नेतन्याहू के गुस्से की एक बड़ी वजह यह भी थी कि इजराइली खुफिया एजेंसी मोसाद और सैन्य अधिकारियों का मानना है कि ईरान युद्ध के दौरान बंद किए गए अपने मिसाइल ठिकानों को फिर से सक्रिय कर चुका है। इजराइल का मानना है कि इस वक्त ईरान पर हमला ना करना उसे परमाणु बम बनाने की खुली छूट देने जैसा है। उधर ट्रंप और नेतन्या की बातचीत को लेकर मचे बवाल के बीच ईरान का भी जवाब आ गया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने एक्स पर लिखा ईरान ने हमेशा अपने वादे को निभाया है। युद्ध को टालने की हर संभव कोशिश की है। हमारी ओर से रास्ते खुले हैं लेकिन दबाव डालकर ईरान को सरेंडर के लिए मजबूर करना सिर्फ एक भ्रम है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स आईआरजीसी ने और भी सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा अगर अमेरिका ने फिर से हमला किया तो वे खाड़ी देशों के तेल की आपूर्ति को सालों के लिए काट देंगे। धमकी यह भी दी कि अगला हमला किसी क्षेत्रीय संघर्ष तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि यह पूरी दुनिया में फैल जाएगा। तो ट्रंप बातचीत की राह पर हैं।

आईटी नियम दूसरा संशोधन, 2026- भारत के डिजिटल शासन की ओर एक बड़ा कदम

वैभव गग्गर, सुकाम्या वहल

भारत का डिजिटल इकोसिस्टम तेजी से विकसित हुआ है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अब लोगों के संवाद करने और जानकारी तक पहुँचते के तरीकों में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। इसने जवाबदेही और ऑनलाइन नुकसान को लेकर नई चुनौतियाँ भी पेश की हैं और मौजूदा नियामक व्यवस्था को तदनुसार विकसित होने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में किए जाने वाले प्रस्तावित बदलाव, जो 30 मार्च, 2026 को प्रकाशित किए गए हैं, भारत की डिजिटल नियामक व्यवस्था में प्रक्रिया से जुड़ी कमियों को दूर करने के लिए एक बड़े कदम को प्रतिबिंबित करते हैं। इन मसौदा संशोधनों का उद्देश्य भाग ढ्ढढ्ढ के तहत मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण, परामर्श और दिशा–निर्देशों के अनुरूप मध्यस्थों के अनुपालन को मजबूत करना और भाग ढ्ढढ्ढढ्ढ के तहत डिजिटल मीडिया से संबंधित कंटेंट नियमन व्यवस्था की नियामक निगरानी के प्रभाव को बढ़ाना है। सबसे पहले, नियम 3(1)(जी) और 3(1)(एच) के तहत डेटा रखरखाव की जिम्मेदारियों के संबंध में स्पष्टीकरण है। प्रस्तावित संशोधन स्पष्ट करता है कि रखरखाव आवश्यकताओं से जुड़े नियमय अन्य लागू कानूनों के तहत निर्धारित जिम्मेदारियों के अतिरिक्त हैं। इससे वह अस्पष्टता दूर होती है जिसने कभी–कभी मध्यस्थों को अलग–अलग या न्यूनतम अनुपालन दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति दी है। आईटी अधिनियम डिजिटल प्लेटफॉर्म को अकेले काम करने की अनुमति नहीं देता। उन्हें आपराधिक प्रक्रिया कानून, वित्तीय नियम और केवल उनके उद्योग पर लागू होने वाले नियमों का भी पालन करना होता है। इस अर्थ में, यह स्पष्टीकरण अर्थपूर्ण और आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण यह कि संशोधन रखरखाव से संबंधित है, पहुँच से नहीं। ऐसे डेटा का खुलासा कानूनी प्रक्रियाओं और सांविधिक सुरक्षा के अधीन रहता है। हालांकि इस प्रकार की एक सामान्य संरक्षण धारा को इस रूप में पढ़ा जा सकता है कि यह उकसाने वाला, अतिव्यापी या यहाँ तक कि मध्यस्थों द्वारा उपयोगकर्ता डेटा के अनिश्चितकालीन रखरखाव के बारे में है, क्योंकि विभिन्न कानूनी दस्तावेज आवश्यकता, उद्देश्य की सीमा या आनुपातिकता का संदर्भ दिए बिना ही ऐसी शर्तें लागू करते हैं। ऐसी चिंताओं को दूर करने के लिए एक स्पष्टीकरण जारी किया जा सकता है, यदि भविष्य में ऐसी चिंता सामने आती है। दूसरा, प्रस्तावित नियम 3(4) को जोड़ना है, जो मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श, स्पष्टीकरण और मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत दायित्वपूर्ण कर्तव्यों के रूप में बाध्यकारी बनाता है। नियमों की धारा 79 से मध्यस्थों को तीसरे पक्ष के कंटेंट की जिम्मेदारी के लिए एक सशर्त सुरक्षित ठिकाना मिल गया था, बशर्ते कि वे उचित प्रक्रिया का पालन करें और गैरकानूनी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग न लें। बड़े पैमाने पर उपयोगकर्ता–कंटेंट पर नजर रखने से बचाने के लिए यह मध्यस्थों के लिए एक ढाल के रूप में काम करता था। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में कहा कि सुरक्षित ठिकाना परंपरागत रूप से मध्यस्थों को तीसरे पक्ष के कंटेंट के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने से बचाता रहा है, जब तक कि वे अवैध गतिविधिा के वास्तविक ज्ञान पर कार्रवाई करते हैं। इस सिद्धांत ने प्लेटफार्मों को जानकारी के प्रवाह में तटस्थ बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन तब से डिजिटल इकोसिस्टम बहुत बदल गया है। प्लेटफार्म अब केवल निष्क्रिय मध्यस्थ नहीं हैं। उनके आकार और एल्गोरिदम उपयोग करने की उनकी क्षमता ने ऑनलाइन नुकसान और लोगों को प्रभावित करने के तरीकों को बदल दिया है। इस स्थिति में, केवल न्यायालय के आदेश या औपचारिक नोटिस पर प्रतिक्रिया देने वाला मॉडल धीरे–धीरे अप्रभावी हो जाता है। नियम 3(4) शासन को अधिक लचीला बनाकर इस कमी को दूर करता है। यह कंटेंट हटाने के लिए कानूनी आदेशों की आवश्यकता को खत्म नहीं करताय इसके बजाय, यह कार्यकारी उपकरणों के माध्यम से, समग्र रूप से प्लेटफॉर्मों के कार्य करने के तरीके को निर्देशित करने का प्रयास करता है। संभावित अतिशयोक्ति के बारे में वैधा चिंताएं हैं, लेकिन तथ्य यह है कि सुरक्षित ठिकाना शर्तों पर आधारित है, इसका हमेशा मतलब रहा है कि उचित कार्रवाई मानक बदल सकते हैं। चीजों को और अधिक वैध बनाने के लिए, यह समझदारी होगी कि इस प्रकार की सलाहें और एसओपी पारदर्शिता के उपायों के साथ जारी किये जाएँ, जैसे प्रकाशन, अच्छी तरह से सोचा गया कारण, और यदि संभव हो तो, हितधारकों से परामर्श। तीसरे, संशोधन प्रस्तावित करता है कि नियम 8.1 की उपधारा को इस तरह बदल दिया जाए कि भाग ढ्ढढ्ढढ्ढ के नियम 14, 15 और 16 न केवल प्रकाशकों पर लागू हों बल्कि मध्यस्थों पर और उपयोगकर्ताओं द्वारा मध्यस्थों के कंप्यूटर संसाधनों पर प्रकाशित समाचार और समसामयिक घटनाक्रम कंटेंट पर भी लागू हों, जो प्रकाशक नहीं हैं। उपयोगकर्ता और प्रकाशक के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं है। यह डिजिटल मीडिया निरीक्षण फ्रेमवर्क के दायरे में एक महत्वपूर्ण विस्तार है, जो पहले मुख्य रूप से समाचार और संकलित कंटेंट के संगठित प्रकाशकों के प्रति केंद्रित था। संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कहीं से भी आने वाले कंटेंट के मामले में गंभीर नियम उल्लंघनों को निपटाया जा सके तथा इसके लिए ऐसे कंटेंट को नियम 14 से 16 में शामिल किया गया है। यह पारंपरिक प्रकाशकों और कार्यात्मक रूप से समान गतिविधियों में लगे डिजिटल–स्थानीय कर्मियों के बीच समानता को और बढ़ावा देता है। इस प्रकार, संशोधन नियामक समानता को बढ़ावा देता है और वर्तमान फ्रेमवर्क में संरचनात्मक कमी को खत्म करता है। इसके साथ ही एक विचारशील फीडबैक बिंदु यह है कि भाग ढ्ढढ्ढढ्ढ का उपयोग उपयोगकर्ता–जनित कंटेंट पर गंभीर और प्रणालीगत नुकसान तक ही सीमित रहना चाहिए। बहुत ज्यादा सख्ती से लागू होने से बचने के लिए, जिससे वैधा राजनीतिक भाषण या लोगों की खोजी पत्रकारिता पर रोक लग सकती है, मंत्रालय यह विचार कर सकता है कि नियम 14 से 16 के तहत मध्यस्थों को लक्षित हस्तक्षेपय स्पष्ट मानदंडों, जैसे पहुँच, प्रभाव और जोखिम के आधार पर किए जाएंगे तथा न्यूनतम प्रतिबंधात्मक उपायों का उपयोग किया जाएगा। यह मध्यस्थ द्वारा समर्थन (होस्ट) दिए गये कंटेंट के निरीक्षण को बेहतर बनाने के घोषित उद्देश्य के साथ–साथ एक खुली और बहुल डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्र को बनाए रखने के उद्देश्य के अनुरूप होगा। अंत में, नियम 14 में प्रस्तावित बदलाव, जिसमें शिकायतों को बदलकर मामले किया गया है, एक प्रतिक्रियाशील से अधिक सक्रिय नियामक दृष्टिकोण की ओर परिवर्तन को दर्शाता है। अंतर–विभागीय समिति (आईडीसी) अब केवल व्यक्तिगत शिकायतों के समाधान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सरकार द्वारा संदर्भ दिए जाने पर व्यापक, प्रणालीगत मुद्दों पर भी विचार कर सकती है। एक ऐसे परिवेश में जहाँ व्यवस्थित तौर पर गलत सूचना फैलाने वाले अभियान जैसे नुकसान अक्सर व्यक्तिगत शिकायतों से आगे चली जाती हैं, यह लचीलापन समयानुकूल और आवश्यक दोनों है। साथ ही, आईडीसी के अधिकार क्षेत्र के विस्तार से प्रक्रियात्मक सुरक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। विचार किए गए मामलों की प्रकृति का समय–समय पर खुलासा, साथ ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन, संस्थागत विश्वसनीयता को मजबूत करेगा और मनमानी हस्तक्षेप की धारणा में कमी लायेगा।

संपूर्ण रूप से देखें तो, मसौदा संशोधन भारत के मध्यस्थता दायित्व व्यवस्था को आधुनिक बनाने का एक व्यावहारिक प्रयास पेश करते हैं।

संक्षिप्त खबरें

आलमबाग पुलिस ने गैर जमानती वारंट के अभियुक्त को किया गिरफ्तार

लखनऊ, (संवाददाता)। पुलिस आयुक्तालय लखनऊ के मध्य जोन के थाना आलमबाग पुलिस दल ने न्यायालय से जारी गैर जमानती वारंट के तहत एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना आलमबाग में मारपीट, गाली–गलौज, धमकी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है।पुलिस के अनुसार अपराधियों और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त मध्य, अपर पुलिस उपायुक्त मध्य तथा सहायक पुलिस आयुक्त कैंट के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक आलमबाग के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान न्यायालय में लंबित वाद संख्या 468@2018 से संबंधित गैर जमानती वारंट के अभियुक्त राहुल को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।गिरफ्तार अभियुक्त राहुल पुत्र कैलाश राम, श्रम विहार नगर मवैया, थाना आलमबाग का निवासी है और उसकी आयु लगभग 28 वर्ष बताई गई है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना आलमबाग में वर्ष 2016 में मारपीट, गाली–गलौज, धमकी और गर्भपात संबंधी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है।पुलिस ने बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उसे वारंट की जानकारी देकर विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक धीरज यादव, मुख्य आरक्षी धीरेन्द्र सिंह तथा आरक्षी मनजीत देशवाल शामिल रहे।

कूटरचित दस्तावेज बनाकर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

लखनऊ, (संवाददाता)। पुलिस आयुक्तालय लखनऊ की मोहनलालगंज कोतवाली पुलिस ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर मकान बेचने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त पर संगठित गिरोह के साथ मिलकर झूठे आश्वासन और फर्जी अभिलेखों के माध्यम से धन हड़पने का आरोप है।पुलिस के अनुसार उन्नाव जनपद के बेहटा नथई सिंह निवासी गायत्री देवी ने थाना पीजीआई में शिकायत दर्ज कराई थी कि सुनील कुमार शुक्ला, रवि सिंह, सर्वेश कुमार पाण्डेय, गौरव अवस्थी, विपिन कुमार शुक्ला, रीतू सिंह, कंचनलता उर्फ अंजना तथा अन्य लोगों ने वृंदावन योजना स्थित मकान बेचने के नाम पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर और झूठे आश्वासन देकर लगभग 73 लाख 99 हजार 911 रुपये हड़प लिए। मामले में थाना पीजीआई में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान पूर्व में चार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा चुकी है।इसी क्रम में नामजद और वांछित अभियुक्त सत्येश प्रशांत पुत्र रामराज, उम्र लगभग 47 वर्ष, को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभियुक्त केनरा बैंक में मंडल प्रबंधक के पद पर कार्यरत बताया गया है। वर्तमान में वह इंदिरानगर क्षेत्र में निवास कर रहा था। पुलिस ने उसे गोरखपुर जनपद के नौका विहार तिराहे के पास से सर्विलांस की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया।पूछताछ में सामने आया कि अभियुक्त ने बैंक पदाधिकारी होने का लाभ उठाते हुए ।

शिवा जी मार्ग व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न

लखनऊ, (संवाददाता)। शिवा जी मार्ग व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को हुसैनगंज स्थित एक होटल में भव्य रूप से सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अमरनाथ मिश्र, चेयरमैन राजेंद्र अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि पवन मनोचा तथा कार्यवाहक अध्यक्ष सतीश अग्रवाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया।इस अवसर पर लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने शिवा जी मार्ग व्यापार मंडल की नई कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हुए दायित्व सौंपे। गोपाल दीक्षित को अध्यक्ष, अंकित शर्मा को वरिष्ठ महामंत्री तथा अभिनव गुप्ता को कोषाध्यक्ष बनाया गया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर वैभव मिश्रा, कपिल सिंघल, संजय गोयल, विक्रम अरोड़ा और देवेंद्र सिंह को जिम्मेदारी दी गई। उपाध्यक्ष पद पर पवन गुप्ता, संजय गुप्ता, विभोर अग्रवाल, आर. मसूद और संदीप गुप्ता को दायित्व मिला।महामंत्री पद पर रितेश अग्रवाल, नीरज त्रिवेदी, गुरदीप सिंह, सुमित गोयल और फहद आलम को जिम्मेदारी सौंपी गई। संयुक्त मंत्री पद पर प्रवीण भगत, सुनील अग्रवाल, शशांक चौरसिया, अंकित अग्रवाल और करण नायर को नामित किया गया, जबकि उमंग खेतान को सह–कोषाध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही अजय भट्ट, अनुराग अग्रवाल, मनीष महाजन, अतुल कुमार गर्ग, अनुभव अग्रवाल, पंकज नंदवानी, रोहित अरोड़ा, शाहबाज खान, मोहित सोनी, वैभव अग्रवाल और वरुण तलवार सहित अन्य सदस्यों को कार्यकारिणी में शामिल किया गया। शंभूनाथ को मनोनीत सदस्य बनाया गया।

अमेठी सैटेलाइट सेंटर में विद्युत उपकेंद्र का उद्घाटन

लखनऊ, (संवाददाता)। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने गुरुवार को अमेठी स्थित सैटेलाइट सेंटर में 33@0.4 केवीए विद्युत उपकेंद्र का उद्घाटन किया। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार यह स्थापना सैटेलाइट सेंटर में चौबीसों घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी तथा शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाएगी।उद्घाटन अवसर पर विशेष कार्याधिकारी प्रो. राज शरण शाही और निदेशक डॉ. संदीप कुमार नायक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. संदीप कुमार नायक द्वारा अतिथियों के स्वागत से हुई।कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने कहा कि सैटेलाइट सेंटर के समग्र विकास के लिए विश्वविद्यालय निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने भविष्य में केंद्र के विस्तार के लिए कई अतिरिक्त आधारभूत संरचना संबंधी कार्य शीघ्र शुरू किए जाने की घोषणा की। इस दौरान सैटेलाइट सेंटर के ऊर्ध्वाधर और समग्र विकास को लेकर विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा भी की गई।विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार प्रो. मित्तल के पिछले एक वर्ष के कार्यकाल में सैटेलाइट सेंटर में अनेक विकास कार्य सम्पन्न हुए हैं। इनमें 20 से अधिक व्याख्यान कक्षों तथा शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यालयों का नवीनीकरण, 60 संगणक प्रणालियों से युक्त संगणक केंद्र की स्थापना, 62 छात्राओं की क्षमता वाले छात्रावास का विकास, 125 सीटों वाले सभागार का नवीनीकरण तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं का विस्तार शामिल है।

'मेडिकल कॉलेज को इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी की ओर से सौंपे गये रक्तदान कार्ड'

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'शाहजहांपुर' इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव डॉ विजय जौहरी ने रक्त संचरण परिषद् के दिशा निर्देश के अनुपालन में शासकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ राजेश कुमार को आठ रक्तदान कार्ड प्रदान करते हुए कहा कि इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी की पहल पर सर्वप्रथम ब्लड बैंक का निर्माण १८३७ में हुआ था। आज विश्व में सबसे अधिक रक्तदाता स्विट्जरलैंड जेनेवा में हैं जहाँ रेडक्रॉस का मुख्यालय भी है। ये रक्तदान कार्ड सड़क दुर्घटना में घायल आपातकालीन स्थिति में रक्त की आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिकता के आधार पर घायल लोगों के लिए है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने ये कार्ड प्रभारी रक्तकोष डॉ ऋतुराज सिंह के सुपुर्द कर दिए, ताकि समय पर जरूरतमंद लोगों को रक्त उपलब्ध कराया जा सके। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ सरोज कुमार ने रेडक्रॉस की इस पहल का स्वागत करते हुए डॉ विजय जौहरी की प्रशंसा की।

कार्यक्रम में रेडक्रॉस सचिव ने कहा कि रक्तदान एक महादान है और रक्तदान से कई लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। संस्था निरंतर समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाने तथा जरूरतमंद मरीजों को सहायता उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने रेडक्रॉस सोसाइटी के इस मानवीय सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास समाज में सेवा और सहयोग की भावना को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर चिकित्सा अधीक्षक डॉ एम० पी० गंगवार,डॉ राजेंद्र कुशवाहा,डॉ ऋतुराज सिंह,डॉ राजेश कुमार,रईस खान हॉस्टल मैनेजर, ललित मोहन मेडिकल कॉलेज आदि लोग मौजूद रहे।

2027 में रहेगा 'सपा मुक्त' का नारा : स्वतंत्र देव सिंह

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शनिवार को जौनपुर में आयोजित कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा का संगठन वर्ष के 365 दिन सक्रिय रहता है। उन्होंने बताया कि दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम उसी सक्रिय संगठनात्मक व्यवस्था का हिस्सा है, जिसमें कार्यकर्ता रात्रि विश्राम भी करेंगे। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भाजपा अन्य राजनीतिक दलों से पूरी तरह अलग है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया "कांग्रेस मुक्त भारत" का नारा अब वास्तविकता में बदल चुका है। उन्होंने कहा कि देश में वंशवाद की राजनीति लगभग समाप्त हो गई है और वर्ष 2027 में "सपा मुक्त" का नारा रहेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल चुनाव के समय सक्रिय नहीं होती, बल्कि पूरे वर्ष जनता के बीच रहकर काम करती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा कानून–व्यवस्था पर उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार करते हुए मंत्री ने कहा कि सपा सरकार में भर्ती के विज्ञापन निकलते ही भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगते थे, जबकि वर्तमान सरकार ने नौ लाख नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से की हैं और कहीं भी भ्रष्टाचार की शिकायत सामने नहीं आई है। उन्होंने किसानों के खातों में सीधे करोड़ों रुपये भेजे जाने का भी उल्लेख किया। जल जीवन मिशन के तहत बन रही पानी की टंकियों के गिरने और भ्रष्टाचार के आरोपों पर मंत्री ने कहा कि पहले बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में ट्रेन से पानी पहुंचता था और महिलाओं को दूर–दूर से पानी लाना पड़ता था, लेकिन अब घर–घर नल से जल पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां भी टंकियां गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं, वहां मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है और दोषियों को जेल भेजने के साथ कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने जैसी कार्रवाई भी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेता अजय राय द्वारा की गई कथित अभद्र टिप्पणी के सवाल पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि, विचार गोष्ठी आयोजित

लखनऊ, (संवाददाता)। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय 'नेहरू भवन' सहित पूरे प्रदेश में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भाग लेकर राजीव गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए।कार्यक्रम में राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी ने राजीव गांधी को सूचना क्रांति का जनक बताते हुए कहा कि आज भारत जिस प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है, उसकी नींव राजीव गांधी ने रखी थी। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया तथा महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान केंद्र सरकार महिला आरक्षण को लेकर केवल राजनीति कर रही है।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अजय राय ने कहा कि राजीव गांधी दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने युवाओं के भविष्य को देश की प्रगति से जोड़ा। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की, संगणक क्रांति को बढ़ावा दिया, उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था को मजबूत किया तथा पंचायती राज कानून लागू कर देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए।अजय राय ने कहा कि कांग्रेस नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी, एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों से सहयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने वर्तमान सरकार पर भी राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया।राजीव गांधी के शिक्षा संबंधी योगदान का उल्लेख करते हुए अजय राय ने कहा कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देशभर में सैकड़ों नवोदय विद्यालय स्थापित कराए, जहां निःशुल्क शिक्षा और सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए अजय राय ने कहा कि राजीव गांधी किसानों को देश की आत्मनिर्भरता की रीढ़ मानते थे। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी का मानना था कि यदि किसान मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। अजय राय ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान में संवेदनशील नहीं रही है।

राजधानी में पारा अब 44 डिग्री के करीब, अब तक का सबसे गर्म दिन

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी में बृहस्पतिवार को भीषण गर्मी और तपिश का प्रकोप रहा। 43.6 डिग्री सेल्सियस के साथ यह सीजन का सबसे गर्म दिन साबित हुआ। दिन और रात में तापमान सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। दोपहर में गर्म पुरवाई के साथ आसमान से जैसे आग बरसनी शुरू हो गई। बढ़े हुए तापमान और हवा में मौजूद नमी ने आग में घी का काम किया। भयंकर तपिश ने प्रचंड गर्मी ने लोगों को असहज और बेचैन किया। राहगीर छांव तलाशते नजर आए और उनका सड़क पर चलना मुहाल था। मौसम विभाग ने शुक्रवार से अगले दो दिनों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। वहीं रातें भी सामान्य से अधिक गर्म होने वाली हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि उत्तरी यूपी से मणिपुर तक एक ट्रफ लाइन गुजर रही है। इस कारण भीषण गर्मी के साथ हवा में मौजूद नमी तकलीफ को बढ़ा रही है। बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़त के साथ 43.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री की बढ़त के साथ 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

भाजपा राष्ट्र निर्माण का माध्यम, कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत : स्वतंत्र देव सिंह

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग में शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा केवल चुनाव जीतने वाली पार्टी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक पवित्र माध्यम है। उन्होंने कहा कि भाजपा की असली ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो समाज सेवा और राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानकर कार्य करते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति ने की। प्रशिक्षण वर्ग में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भाजपा अन्य राजनीतिक दलों से अलग विचारधारा पर चलने वाला संगठन है, जिसका उद्देश्य देश के सांस्कृतिक गौरव को पुनर्स्थापित करना और राष्ट्र को सशक्त बनाना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को 'राष्ट्र प्रथम' का संकल्प दिलाते हुए कहा कि भाजपा में व्यक्ति नहीं, बल्कि विचारधारा और संगठन सर्वोपरि होता है। उन्होंने कहा कि दल से बड़ा देश है और यही भावना भाजपा को विशिष्ट बनाती है। कार्यकर्ताओं से उन्होंने सादगी, विनम्रता और सेवा भाव के साथ जनता के बीच रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता जनता के सुख–दुख के सहभागी बनें और सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। जल शक्ति मंत्री ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि 'हर घर नल से जल', मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से लाभार्थियों के साथ सतत संपर्क बनाए रखने और पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने का आग्रह किया। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने संगठन में अनुशासन और शुचिता पर बल देते हुए कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलकर भाजपा आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बनी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अहंकार से दूर रहकर सेवा को ही अपना मूल मंत्र बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर गिरीश चन्द्र यादव राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रमेश मिश्र विधायक बृजेश सिंह मनीष शुक्ला प्रदेश प्रवक्ता के पी सिंह पूर्व सांसद महेश चन्द्र श्रीवास्तव पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष काशी प्रांत अशोक चौरसिया सुशील उपाध्याय पूर्व गृह राज्य मंत्री वरिष्ठ बीजेपी नेता कृपाशंकर सिंह अजय शंकर दुबे पीयूष गुप्ता महामंत्री संदीप तिवारी अजय सिंह मनोरमा मौर्य नगर पालिका परिषद अध्यक्ष गीता बिंद महिला आयोग सदस्य,आमोद सिंह मीडिया प्रभारी,रोहन सिंह आईटी सेल , अमित श्रीवास्तव पूर्व नगर अध्यक्ष,रागिनी सिंह जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा,विमला श्रीवास्तव, डॉ अंजना श्रीवास्तव आदि तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहें।

राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव का कांग्रेस पर पलटवार

बोले, कांग्रेस हताश, पीएम का अपमान कर रही अखिलेश पर भी साधा निशाना

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से हताश हो चुकी है और देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रही है। राज्यमंत्री यादव ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो लोकतंत्र में निंदनीय है। उन्होंने जोर दिया कि लोकतांत्रिक आचरण संसदीय मर्यादाओं के भीतर होना चाहिए और उन सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। यादव ने अजय राय द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा की निंदा करते हुए उनसे प्रधानमंत्री से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री की मां के खिलाफ असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया था, तो बिहार की जनता ने चुनाव में अपने मत के माध्यम से इसका जवाब दिया था। यादव ने कहा कि इसी तरह देश की जनता भी ऐसे आचरण और व्यवहार का जवाब देगी, जो संसदीय मर्यादा का उल्लंघन करता है। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए राज्यमंत्री ने कहा कि जब वह सत्ता में थे, तब कोई बोर्ड नहीं बना पाए और न ही जनता को कोई राहत दिला पाए। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार पहले ही व्यापारी कल्याण बोर्ड बना चुकी है और उसमें सदस्यों को नामित भी कर चुकी है। यादव ने अखिलेश यादव को हताश और निराश बताते हुए कहा कि उन्हें सत्ता विरासत में मिली थी, जनता का जनादेश कभी नहीं। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन को 75 सीटें मिलने, 2017 में दो–तिहाई बहुमत और श्बुआ–बबुआश् (बसपा–सपा) के साथ लड़ने पर भी 64 सीटें मिलने का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि हर चुनाव में भाजपा को जीत मिली है, जो जनता के जनादेश और भाजपा की वैचारिक विचारधारा व नीतियों के पक्ष में है। राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव ने भविष्यवाणी की कि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रदेश से पूरी तरह साफ हो जाएगी।

अवांती पेट केयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लखनऊ में भव्य ब्रीडर मीट का आयोजन

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। पेट न्यूट्रिशन एवं पेट हेल्थ के क्षेत्र में कार्यरत कंपनी ," अवंती पेट केयर प्राइवेट लिमिटेड ", के प्रीमियम ब्रांड ," अवंत फर्स्ट" पेट फूड द्वारा लखनऊ में एक भव्य डॉग एवं कैट ब्रीडर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें 70 से अधिक डॉग एवं कैट ब्रीडर्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन कंपनी के रीजनल मैनेजर ,"ब्रज पाठक " एवं एरिया मैनेजर ," अंशुमान मालवीय" द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान ब्रीडर्स के साथ पालतू पशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। विशेषज्ञों द्वारा बताया गया कि पालतू पशुओं के लिए संतुलित आहार कितना आवश्यक है तथा प्रोटीन, 37 आवश्यक विटामिन्स, ऑयल, पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट एवं अन्य पोषक तत्व उनके सम्पूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही गर्मियों में पेट्स की देखभाल, क्या खिलाना चाहिए एवं किन चीजों से बचना चाहिए, स्किन एवं कोट हेल्थ, ब्रेन डेवलपमेंट, बोन स्ट्रेंथ, डाइजेशन, वजन नियंत्रण एवं अलग–अलग लाइफ स्टेज में आवश्यक न्यूट्रिशन की जानकारी भी साझा की गई। कार्यक्रम में पेट ब्रीडिंग मैनेजमेंट एवं वैक्सीनेशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गईं। कंपनी टीम द्वारा बताया गया कि आवश्यक पोषक तत्वों के साथ ग्लूकोसामीन, युक्का, एल–कार्निटीन एवं क्रैनबेरी जैसे तत्व शामिल हैं, जो पेट्स की बेहतर ग्रोथ एवं हेल्थ के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। साथ ही इसकी 95: से अधिक पैलेटेबिलिटी होने के कारण पेट्स इसे काफी पसंद करते हैं। कंपनी ने बताया कि प्रीमियम क्वालिटी डॉग एवं कैट फूड को किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराया रहा है, जो 400 ग्राम, 1 किलो, 2.8 किलो, 6.5 किलो, 10 किलो एवं 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध है। पूरा कार्यक्रम पेट पैरेंटिंग, न्यूट्रिशन एवं बेहतर सेवाओं से संबंधित ज्ञानवर्धक चर्चाओं से भरपूर रहा। सभी प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता की एवं सत्र का भरपूर आनंद लिया। इस महत्वपूर्ण उपस्थिति के लिए सभी ब्रीडर का अवंत फर्स्ट के अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर अदीब शेख ने आभार व्यक्त किया।

चोरी की बाइक पर भर रहा था फर्राटा, गिरफ्तार

गोरखपुर, (संवाददाता)। पुलिस ने चोरी की बाइक से वारदातों को अंजाम दे रहे लूट के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान पटाखा चौराहा निवासी राकेश पासवान के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से चोरी की बाइक और छह हजार रुपये नकद बरामद किए हैं। कार्रवाई के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने बीते फरवरी माह में कौड़ीराम स्थित एक मैरिज हॉल के बाहर खड़ी बाइक चोरी की थी। इसी बाइक का उपयोग कर वह और उसका साथी सिकरी जंगल निवासी गोलू उर्फ विकास पासवान लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों ने 15 अप्रैल को तिलकोत्सव समारोह में पति और बच्चे संग जा रही सिकरीगंज के एकड़ंगा दयाराम दूबे निवासी महिला के गले से मंगलसूत्र छीन लिया था। वारदात रात करीब 9:15 से 9:25 बजे के बीच हुई थी, जिसमें बदमाश बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार थे और पीछे बैठे आरोपी ने अपना चेहरा गमछे से ढक रखा था। ऐसे ही 24 अप्रैल को तेनुआ टोल प्लाजा के पास बेलीपार के महावीर छपरा बडेरिया निवासी शीला मौर्या से भी इसी तरह मंगलसूत्र छिनैती की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी छीने गए आभूषणों को नेपाल में बेचकर रकम आपस में बांट लेते थे। फिलहाल पुलिस गोलू उर्फ विकास पासवान की तलाश में जुटी है।

ट्रोल–डीजल की किल्लत, गैलन लेकर लाइन में लगे लोग–शहर के ज्यादातर पंप ड्राई

गोरखपुर, (संवाददाता)। गोरखपुर में पेट्रोल–डीजल की किल्लत लगातार बनी हुई है। बृहस्पतिवार सुबह से ही गैलन लेकर पंपों पर लोगों की भीड़ लगी रही। शहर के ज्यादातर पंप ड्राई हो गए हैं। अचानक ईंधन सप्लाई ठप होने से हड़कंप मच गया। सुबह से ही शहर के प्रमुख पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। कई पंपों पर श्पेट्रोल–डीजल खत्मश का बोर्ड लगा दिया गया। जिन पंपों पर थोड़ा–बहुत स्टॉक बचा था, वहां अफरातफरी का माहौल रहा। अचानक ईंधन संकट से स्कूली वाहन, एंबुलेंस, दफ्तर जाने वाले और रोजमर्रा के काम से निकले लोग परेशान दिखे। कई लोग गैलन लेकर एक पंप से दूसरे पंप का चक्कर काटते रहे। फिलहाल पंप ड्राई होने का स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। सप्लाई बाधित होने या अचानक मांग बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

टावर पर चढ़ी दो युवतियां, मचा हड़कंप, प्रशासन के हाथ–पांव फूले

गोरखपुर, (संवाददाता)। महराजगंज में नगर पालिका परिषद महराजगंज के सरोजनी नगर वार्ड स्थित सूचना कार्यालय के समीप उस समय हड़कंप मच गया, जब दो युवतियां मोबाइल टावर पर चढ़ गईं। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है, जबकि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी युवतियों को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में लगे हुए हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि टावर पर चढ़ी युवतियों में एक पंजाब की रहने वाली बताई जा रही है, जो स्थानीय एक आर्केस्ट्रा में डांसर के रूप में कार्य करती है। दूसरी युवती की पहचान और उसके संबंध में जानकारी जुटाने का प्रयास पुलिस कर रही है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व उक्त युवती ने आर्केस्ट्रा संचालक के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपित को जेल भेज दिया था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि उसी मामले या किसी अन्य विवाद को लेकर युवतियां टावर पर चढ़ी हैं। हालांकि, अभी तक उनके टावर पर चढ़ने के पीछे की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा–तफरी का माहौल बना हुआ है। पुलिस लगातार युवतियों को समझाने–बुझाने में जुटी हुई है। सदर कोतवाल निर्भय कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार को करीब साढ़े सात बजे दो युवतियों के मोबाइल टावर पर चढ़ने की सूचना मिली थी। इसके बाद तत्काल उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया और युवतियों को सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है।

सेमीफाइनल में पहुंचीं हिलौली, पश्चिमगांव और अकोहरी

उन्नाव, (संवाददाता)। ब्लॉक हिलौली के बचुआखेड़ा स्थित ग्रामीण स्टेडियम में चल रही एचपीएल ग्रामीण नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता में बुधवार की रात चार मुकाबले खेले गए। इसमें हिलौली, पश्चिमगांव और अकोहरी की टीमों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। पहले मैच में हिलौली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 104 रन बनाए। जवाब में दादूखेड़ा की टीम 86 रन ही बना सकी। हिलौली ने 18 रन से जीत दर्ज की। अमित शुक्ला को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके बाद पहला क्वार्टर फाइनल मैच बरदहा और पश्चिमगांव के बीच हुआ। पश्चिमगांव ने 85 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में बरदहा की टीम 40 रन ही बना सकी। निशांत को मैन ऑफ द मैच चुना गया। दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच अकोहरी और मदाखेड़ा के बीच खेला गया। मदाखेड़ा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 67 रनों का लक्ष्य दिया। अकोहरी ने यह लक्ष्य आसानी से हासिल कर जीत दर्ज की। मयंक यादव को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। तीसरा क्वार्टर फाइनल हिलौली और भागीखेड़ा के बीच खेला गया, जिसमें हिलौली ने 109 रन बनाकर भागीखेड़ा को 85 रन पर आउट कर 24 रन से जीत दर्ज की। शिवम पाल को 45 रनों की धुआंधार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। सचिन कुशवाहा और अंकित श्रीवास्तव ने मैचों में अंपायरिंग की। डॉ. सुशील कुमार, वीरभान, विकास सिंह, नागमणि, सुधांशु द्विवेदी, अनोज शुक्ला, मुकेश निर्मल, धीरू दीक्षित, रामशंकर लोधी, शुभम सिंह और जय सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

पुल की मरम्मत में लापरवाही, दिन में जाम, रात में हो रहे हादसे

उन्नाव, (संवाददाता)। शहर में जाम इस भीषण गर्मी में और मुसीबत बन गया है। एक महीने से चल रही हरदोई रोड पुल की मरम्मत का आधा काम भी खत्म नहीं हो सका है। वहीं सदर बाजार में दो महीने पहले पाइप लाइन शिफ्टिंग के लिए खोदी गई सड़क की मरम्मत न होने से यातायात बाधित रहता है।मालूम हो कि शहर में हरदोई रोड पुल के स्लैब जॉइंट के एंगल बदलने का काम चल रहा है। एक महीने से चल रहा यह काम अभी आधा भी नहीं हो पाया है। आधा रास्ता बंद करके कराई जा रही मरम्मत से दिन भर यातायात प्रभवित रहता है। एक–एक तरफ के वाहनों को बारी–बारी निकाला जा रहा है। निर्माण स्थल पर रात के समय रोशनी और संकेतक न होने से हादसों का खतरा बना रहता है। अक्सर लोग अंधेरे में गड्ढे और निर्माण सामग्री नहीं देख पाते और गिरकर घायल होते हैं। बुधवार रात बाइक से मोतीनगर जा रहे सिविल लाइंस निवासी राहुल दीक्षित,अंधेरे में दूर से गड्ढा नहीं देख पाए और चपेट में आकर गिरकर घायल हो गए। वहीं दो महीने पहले बड़ा चौराहा सदर बाजार में भूमिगत पाइप लाइन शिफ्ट करने लिए खोदी गई सड़क की मरम्मत न होने से यातायात बाधित रहता है और दिन में कई बार जाम भी लगता है। पुल की मरम्मत का काम तेजी से पूरा कराने के लिए निर्माण एजेंसी को निर्देश पहले ही दिए गए हैं। यातायात सुरक्षा के भी प्रबंध पूरे करने को कहा गया था। रात में पर्याप्त रोशनी और संकेतक भी लगवाए जाएंगे।

महिला पुलिस कर्मियों ने मिशन शक्ति अभियान के तहत किया जागरूक

अयोध्या।शनिवार को महिला पुलिस कर्मियों ने जिला महिला चिकित्सालय,जिला पुरुष चिकित्सालय, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन सहित अन्य प्रमुख चौराहों तथा मार्गों पर मिशन शक्ति अभियान फेज – 5 के तहत महिलाओ व अन्य लोगो को जागरुक किया है।इस मौके पर उन्होंने महिलाओ व बेटियों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति जागरूक व सुरक्षात्मक उपाय भी बताई।इस मौके पर उन्होंने महिलाओं तथा बालिकाओं को सुरक्षात्मक टिप्स की भी जानकारी दिया।इस मौके पर उन्होंने विधवा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जिसमे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं सुकन्या समृद्धि योजना और हेल्पलाइन नंबर के बारे में महिलाओं को जागरूक किया।इसके अलावा उन्होंने उन्हें किसी भी प्रकार की पुलिस सहायता हेतु विमेन पावर लाइन 1090, यूपी 112, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड लाइन 1098, साइबर अपराध 1930 के बारे में बताया गया।बताया कि यह सभी नंबर आप लोग हमेशा याद रखें। जब भी आपको किसी भी प्रकार की सहायता लेने की जरूरत हो तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं।इस मौके पर महिला कांस्टेबल वंदना यादव,रिक्रूट महिला कांस्टेबल लक्ष्मी सोनी मौजूद रहे।

कनक किड्स और सरयू इंटरनेशनल स्कूल मे पाँच दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन शुरु

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर स्थित कनक किड्स इंटरनेशनल स्कूल मे आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआस कार्यक्रम में कनक किड्स इंटरनेशनल स्कूल एवं सरयू इंटरनेशनल स्कूल के शिक्षकों को नई शिक्षा नीति आधुनिक शिक्षण तकनीक तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास से संबंधित जानकारियां प्रदान की गईस ओरिएंटेशन कार्यक्रम मे जे.बी. ए. के पूर्व प्रिंसिपल अशोक कुमार तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेसविद्यालय परिवार द्वारा उनका स्वागत एवं सम्मान किया गया।उन्होंने शिक्षकों को नवीन शिक्षण पद्धतियों,प्रभावी शिक्षण गुणो तथा विद्यार्थियों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए।कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रभावी शिक्षण तकनीक कक्षा प्रबंधन तथा विद्यार्थियों के बौद्धिक एवं नैतिक विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से प्रकाश डालास उन्होंने शिक्षकों को शिक्षा के बदलते स्वरूप के अनुरूप स्वयं को निरंतर अपडेट रखने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया।इस अवसर पर कनक किड्स एवं सरयू इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन डॉ संजय तिवारी, डायरेक्टर डॉ.मधु त्रिपाठी हेडमिस्ट्रेस प्रीति सिंह, वाइस प्रिंसिपल प्रगति श्रीवास्तव तथा दोनों विद्यालयों के शिक्षक गण अनीता सिंह, फरजाना फातिमा, वंशिका शुक्ला, राधिका पाठक, प्रिया सिंह,श्रद्धा ठाकुर अलका पांडे,शशि मिश्रा रिचा आनंद अंजली मिश्रा,साक्षी यादव,रिंकी सिंह, अजीता तिवारी, सीमा, निकिता सहदेव,रश्मि तिवारी, राशी शुक्ला,हर्षिता त्रिपाठी,गौरी मिश्रा पूजा सिंह, चंदन सिंह अविनाश कश्यप अस्तित्व श्रीवास्तव निधि श्रीवास्तव निधि श्रीवास्तव दीपक शर्मा उपस्थित रहे।

लू व तेज धूप के चलते भारी संख्या में जिला चिकित्सालय मे आ रहे मरीज

अयोध्या। इस समय लू और तेज धूप से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है।इस समय सबसे अधिक लोग डायरिया सहित तेज बुखार से पीड़ित हो रहे हैं।देखा जाए तो इस समय डायरिया तथा तेज बुखार से पीड़ित मरीज भारी संख्या मे जिला चिकित्सालय के साथ–साथ निजी चिकित्सालय में भर्ती हो रहे हैं।इधर पिछले एक सप्ताह से भीषण गर्मी तथा तेज धूप के चलते लोग डायरिया तथा तेज बुखार से पीड़ित हो रहे हैं।जिसके चलते शनिवार को जिला चिकित्सालय व निजी चिकित्सालय में इलाज कराने आने वाले लोगों की भारी संख्या में भीड़ दिखाई दे रही थी।इन रोगियों में सबसे अधिक संख्या बच्चों व बुजुर्गों की रही।यही हालत जिला चिकित्सालय के नमें बच्चा वार्ड की रही।इस संबंध में प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डाक्टर राजेश सिंह ने लोगो से अपील किया कि कि इस समय काफी सतर्कता बरतने की जरुरत है।लोगो को सलाह दिया कि लोग कोशिश यही करे कि सुबह दस बजे के बाद और शाम चार बजे के पहले बाहर न निकले। तेज धूप व लू से बचने के लिए शरीर को पूरी तरह से कपड़ों से ढके तथा छाता व टोपी का प्रयोग करें। चिकित्सकों ने लोगों से अपील किया कि इस समय अधिक से अधिक नीबू पानी,खीरा,ककड़ी, पपीता, नींबू, दही, पानी चीनी व नमक का घोल, मट्ठा छाछ लस्सी बेल का शर्बत सहित अन्य शीतल पेय पदार्थों का सेवन करे।

सीएम योगी के सामने यूपी टीम ने 36 साल बाद जीता स्वर्ण, क्वाड्रपल स्कल में किया कमाल

गोरखपुर, (संवाददाता)। गोरखपुर का रामगढ़ताल गुरुवार को उत्तर प्रदेश रोइंग के इतिहास में सुनहरे अध्याय का साक्षी बना। 46वीं जूनियर नेशनल रोइंग चौंपियनशिप के आखिरी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मेजबान उत्तर प्रदेश की बालक क्वाड्रपल स्कल टीम ने 36 साल के सूखे को खत्म किया और स्वर्ण जीता। इस वर्ग के फाइनल में जैसे ही यूपी के रोइंग खिलाड़ियों की नाव ने फिनिशिंग लाइन पार की, पूरा रामगढ़ताल मुख्यमंत्री की मौजूदगी में तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मुख्यमंत्री ने खुद इस रोमांचक मुकाबले का गवाह बनते हुए खिलाड़ियों के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन की सराहना की और उनका हौसला बढ़ाया। बालक क्वाड्रपल स्कल में यूपी के दीपक कुमार, यश कुमार यादव, हरिनाथ यादव व प्रवीण कुमार ने अपना सब कुछ झोंक दिया और पहले स्थान पर रहे। इस स्वर्ण के चलते यूपी को बालक वर्ग में तीसरा स्थान मिला। इससे पहले 1990 में लखनऊ में हुई राष्ट्रीय जूनियर चौंपियनशिप में बालक पेयर्स में हरपाल सिंह औक नफीस अहमद की जोड़ी ने रजत पदक जीता था। बालक क्वाड्रपल स्कल में केरल के गौतम कृष्णा, आगस्टिन, तलवार सिंह व एचएम नायर की टीम को रजत पदक और आर्मी ब्वायज स्पोर्ट्स कंपनी के अर्णव रावत, दिलशाद खान, प्रथमेश व गगनदीप सिंह को कांस्य पदक मिला। चौंपियनशिप के बालक वर्ग में आर्मी ब्वायज स्पोर्ट्स कंपनी दो स्वर्ण, एक रजत व एक कांस्य के साथ और बालिका वर्ग में मध्य प्रदेश ने दो स्वर्ण, एक रजत व एक कांस्य के साथ चौंपियनशिप ट्रॉफी जीती। मुख्यमंत्री ने बालिका डबल स्कल के फाइनल को भी देखा। जिसमें महाराष्ट्र की शिवरानी कटेरिया व आरुषी बरार ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि मध्य प्रदेश की वंशिका साहू व प्रियंका ने रजत व मणिपुर की एल रोशबिना देवी व स्वेयिया हैसनाम ने कांस्य पदक जीता। फाइनल के अन्य मुकाबलों में बालिका सिंगल स्कल में मध्य प्रदेश की संतोष यादव ने स्वर्ण, ओडिशा की नेहा ने रजत व महाराष्ट्र की इश्वरी ने कांस्य पदक जीता। बालक काक्सलेस पेयर्स में हरियाणा के नितिन व करन शहरान ने स्वर्ण, आर्मी ब्वायज स्पोर्ट्स कंपनी के नितिन कुमार व जसवंत सिंह ने रजत व मध्य प्रदेश के अयान यादव व अनुराग वर्मा ने कांस्य पदक जीता। बालिका क्वाड्रुपल स्कल में केरल की अनालिया विल्सन, लाया विनोज, एंजल मैरी थामस, हरिप्रिया विनेश की चौकड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। ओडिशा की शिवानी, स्मृति इक्का, प्रतिज्ञा जेना व रितुरानी ने रजत एवं आरएफआई –हिमाचल की अनामिका ठाकुर, तनिष्का ठाकुर, अर्चिता नेगी व श्रेया ठाकुर ने कांस्य पदक जीता। बालक काक्सलेस पेयर्स में आर्मी ब्वायज स्पोर्ट्स कंपनी के इशू सतपाल, संदीप सांगवान, मोहित, सागर की टीम ने स्वर्ण, हरियाणा के अरमान, नितिन, अरमान लोहान, गगन ने रजत और मध्य प्रदेश के राज कमारिया, श्लोक डांगी, हरिओम, अरुण गुर्जर ने कांस्य पदक जीता।

श्रद्धालु के कार को ट्रेलर ने मारी टक्कर, हाईवे पर रहा घंटों जाम

अयोध्या शनिवार को प्रतापगढ़ से अयोध्या दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं की कार को ट्रेलर ने लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर पंचशील होटल के समीप टक्कर मार दिया। हादसे में कर तो छतिग्रस्त हो गई लेकिन कर सवार श्रद्धालुओं को किसी तरह की चोट नहीं लगी।कार में सात श्रद्धालु शामिल रहे।हादसे के बाद हाइवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात प्रभावित हो गया।हादसे की सूचना मिलते ही देवकाली चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और जाम को खुलवाकर यातायात सुचारु कराया।पुलिस ने ट्रेलर चालक को हिरासत में ले लिया है।

कई थाना क्षेत्रों मे दीवारों पर लिखे पुलिस कर्मियों के सीयूजी नंबर अब मिटने की कगार पर

अयोध्या। जिले के लोगों को अपने–अपने थानों के प्रभारी निरीक्षकध्थानाध्यक्ष,चौकी प्रभारी व बीट प्रभारी का सीयूजी मोबाइल नंबर याद रहे।जिससे अपराध से संबंधित जानकारी समय रहते पुलिस को दे सके और अपराध होने से बचे।इसके लिए पूर्व मे एसएसपी रहे आशीष तिवारी ने शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों मे इन पुलिस कर्मियों के सीयूजी मोबाइल नंबर दीवारों पर लिखवाये थे।इस नंबर को आज भी कही कही जगहों पर देखा जा सकता है।उन्होंने लोगों से अपील किया था कि अगर आप सभी को किसी भी तरह की आपराधिक घटनाओं की सूचना पुलिस को देना हो तो वे दीवालों पर लिखे संबंधित प्रभारी निरीक्षकध्थानाध्यक्ष,चौकी प्रभारी व बीट के पुलिस कर्मियों को दे सके।परंतु दीवालों पर लिखा यह सीयूजी नंबर अब निष्क्रिय ही दिखाई दे रहा है।पहले यह सीयूजी नंबर कोतवाली नगर,कोतवाली अयोध्या, थाना राम जन्मभूमि,पूराकलंदर, कोतवाली बीकापुर, महाराजगंज, गोशाईगंज, इनायत नगर, रूदौली, रौनाही,कैंट,हैदरगंज, तारुन सहित सभी थाना क्षेत्रो के आसपास तथा उन थाना क्षेत्र के बाजरो ग्रामीण अंचलों मोहल्लों कॉलोनी में भी यह सीयूजी नंबर दीवारों तथा गुमटियों पर लिखा रहता था।इस समय सभी थाना क्षेत्रों में लिखे गए दीवालों पर संबंधित बीट के पुलिस कर्मियों का सीयूजी मोबाइल नंबर निष्क्रिय दिखाई दे रहा है।

एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी के अवैध कट को किया बंद

उन्नाव, (संवाददाता)। लखनऊ–आगरा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी के अवैध कट यूपीडा के कर्मचारियों ने बंद कर दिए हैं। इससे कई गांवों के लोगों को चार किलोमीटर दूर अंडरपास से आना–जाना होगा। हालांकि अवैध कट बंद होने से हादसों पर अंकुश लगेगा। लखनऊ–आगरा एक्सप्रेसवे पर खंभौली गांव के सामने साढ़े तीन किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण कराया गया है। हवाई पट्टी की सर्विस रोड पर गोसाईं बाबा का मंदिर होने के साथ ही कई दुकानें और होटल संचालित हैं। यहां 20 मीटर तक सभी सुरक्षा उपकरणों को काटकर लोगों ने अवैध कट बना लिया था। इससे चालक ट्रक, डीसीएम, कार और बसों को हवाई पट्टी पर खड़ा कर ढाबों और होटलों में खाने–पीने चले जाते थे। वाहन कई घंटे तक हवाई पट्टी पर ही खड़े रहते थे। इन वाहनों से अन्य वाहन आकर टकरा जाते थे। साथ ही खंभौली, कबीरपुर, अमीरपुर और गंभीरपुर सहित कई गांवों के लोग इसी कट से एक्सप्रेसवे को पार करते थे। इससे कई बाद दुर्घटना हो जाती थी। यूपीडा ने कई बार अवैध कट बंद करने की औपचारिकता निभाई लेकिन राहगीर बार–बार कट को खोल देते थे। इस पर एसडीएम बृजमोहन शुक्ला ने यूपीडा को अवैध कट पूरी तरह बंद करने के निर्देश दिए थे। बृहस्पतिवार को यूपीडा ने कट को सुरक्षा जाली और लोहे के गार्ड लगाकर बंद कर दिया। कट बंद से आसपास के गांवों के लोगों को बांगरमऊ–संडीला मार्ग के ओवरब्रिज से होकर चार किमी का लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। यूपीडा के सुरक्षा अधिकारी एके चंदेल ने बताया कि इस बार इस बड़े कट को पूरी सुरक्षा के साथ बंद किया गया है। कट के बंद होने से हवाई पट्टी पर खड़े वाहनों के कारण होने वाली घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगेगी।

जिंदा जलकर मरी थी कूड़े के ढेर में मिली युवती

उन्नाव, (संवाददाता)। कानपुर–लखनऊ हाईवे किनारे कूड़े के जलते ढेर में मिले युवती के शव का बृहस्पतिवार को पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया। शव पूरी तरह जला मिला है। सांस नली में धुआं होने से जिंदा जलने से मौत की पुष्टि हुई है। दाहिने हाथ में फ्रैक्चर भी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मौत से पहले वह 40 से 45 मिनट तड़पी होगी। जिंदा जलाकर मारने के बिंदु पर पुलिस जांच कर रही है। हालांकि युवती की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। एआरटीओ कार्यालय के सामने और एक होटल से 100 मीटर दूर सोमवार को कूड़े के ढेर में करीब 25 साल की युवती का शव नग्न अवस्था में जलते कूड़े के ढेर में मिला था। दुष्कर्म या किसी रंजिश के चलते हत्या के अंदेशे पर पुलिस की दो टीमें जांच में लगी हैं। बृहस्पतिवार को शव का पैनल में शामिल मौरावां अस्पताल के डॉ. सिंह विक्रम कटियार और पुरवा सीएचसी के डॉ. उमेंद्र कुमार ने पोस्टमार्टम किया। शव शत–प्रतिशत जला पाया गया। सांस नली में धुआं होने से जलने से मौत की बात सामने आई है। शव पूरी तरह जला होने से दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हो सकी है। पहचान न होने पर डीएनए जांच के लिए सैंपल सुरक्षित किया गया है। उधर कोतवाली पुलिस खुलासे के लिए एआरटीओ कार्यालय और हाईवे पर अलग–अलग स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांच रही है। कोतवाल चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। खुलासे के लिए टीमें लगी हैं। जल्द ही घटना का खुलासा होगा। घटना के बाद पुलिस ने मामले को दबाने का खूब प्रयास किया। घटनास्थल पर कुछ लोगों ने वीडियो बनाए तो कोतवाली पुलिस ने उनके मोबाइल फोन छीनकर फोटो और वीडियो डिलीट करा दिए थे।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।